जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 16 संख्याः 233 प्रभात हिण्डौन सिटी, गुरुवार 27 जून, 2024 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

संसद के पहले ही दिन मोदी ने ''मैसेज'' दिया कि, वे अपने ही तरीके से काम करेंगे

- लोकसभा स्पीकर बनने के बाद, ओम बिड़ला ने 1975 के आपालकाल की भर्त्सना करते हुए, वक्तव्य दिया, जिसमें इंदिरा गांधी की प्रजातंत्र का गला घोटने, जनता के ''सिविल राइट्स'' (नागरिकता के अधिकार) को कुचलने व विपक्ष के नेताओं को जेल मे डालने का आरोप लगाया।
- इस वक्तव्य के पश्चात् ओम बिड़ला ने आपातकाल के विरोध मे एक मिनट ''साइलैंस'' भी रखा सदन में।
- इन कृत्यों से मोदी सरकार ने स्पष्ट मैसेज भी दिया कि, वे सदन के अंदर व बाहर, विपक्ष से समझौते या बातचीत का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि, सामना करने का रवैया रखेंगे।
- विपक्ष का इस बारे में यह मानना है कि, मोदी का यह रवैया, इस बात का सूचक है कि, वे राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन से खास खफा हैं, चुनाव के दौरान यह प्रचार करने के लिये कि, मोदी संविधान बदलना चाहते हैं और संविधान बदलकर, एस.सी., एस.टी. का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। एस.सी. में फैली इस ''खबर'' का यू.पी., राजस्थान, हरियाणा में दलित वोट भाजपा के खिलाफ हो गया और भाजपा को काफी नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। नरेन्द्र मोदी समय बर्बाद करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अठारहवीं लोकसभा के पहले दिन प्रधानमंत्री ने सर्वसम्मत या सहयोग का नहीं बल्कि टकराव का संदेश दे दिया और इसके साथ ही संसद तथा उसके बाहर भविष्य के युद्ध का मंच तैयार किया।

उन्होंने विपक्ष तथा विशेष रूप से राहुल के विरुद्ध लोकसभा के नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिड़ला के माध्यम से एक मिसाइल दागी। आज सुबह ही, विपक्ष के प्रत्याशी, कांग्रेस के सांसद के. सुरेश को हराकर ओम बिड़ला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए।

स्पीकर के रूप में अपने पहले कार्य के रूप में, ओम बिड़ला ने तैयार किया हुआ एक बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें आपातकाल के काले दिनों, इन्दिरा गाँधी की भूमिका की भारी आलोचना की। इसके अलावा, कैसे प्रजातंत्र का नाश किया गया, कैसे नागरिक स्वतंत्रता व अधिकारों को रौंदा गया, कैसे विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, आदि विषयों पर भी ओम बिड़ला बोले।

फिर स्पीकर ने आपातकाल पर एक मिनट का मौन रखने के लिए कहा।

स्पष्ट है कि, नरेन्द्र मोदी बहुत उद्विग्न हैं तथा राहुल गाँधी, कांग्रेस व विपक्ष पर पलटवार करना चाहते हैं, उनके इस अभियान को लेकर कि, मोदी संविधान बदलना चाहते हैं।

उक्त अभियान के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा अन्य प्रमुख राज्यों में दलितों ने भाजपा के विरुद्ध मतदान किया, जिसके कारण मोदी तथा भाजपा को लोकसभा में अपना बहुमत खोना पड़ा।

नड्डा ने आपातकाल के विरुद्ध इस सप्ताह के देशव्यापी अभियान की घोषणा की है, जो कि 49 वर्ष पूर्व हुई एक घटना को लेकर मोदी का जवाब है।

नरेन्द्र मोदी ने संकेत दे दिया है, कि वे ऐसे आदमी नहीं जो बदल जाएंगे वे अपनी शर्तों पर काम करते रहेंगे भले ही अब उनके खिलाफ विपक्ष की ताकत बढ़ गई हो।

राहुल इस समय विपक्ष के नेता हैं उन्होंने अन्य नेताओं के साथ स्पीकर से

(शेष पृष्ठ 5 पर)

कन्हैया हत्याकांड में पुलिसकर्मी ने गवाही दी

जयपुर, 26 जून (का.सं.)। एनआईए मामलों की विशेष अदालत में बुधवार को उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के बयान दर्ज कराए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से भीम पुलिस थाने के जीप चालक कांस्टेबल शंकर लाल ने बयान में हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पकड़ने की जानकारी अदालत को दी।

शंकरलाल ने अपने बयान में

- भीम पुलिस थाने के जीप ड्राइवर कांस्टेबल शंकर लाल ने बताया कि, उन्हें कन्हैया लाल की हत्या के आरोपियों द्वारा उदयपुर से अजमेर जाने की जानकारी मिली थी, तब पुलिस ने नाकाबंदी लगाकर उन्हें पकड़ा।

बताया कि, उन्हें सूचना मिली थी कि, कन्हैयालाल की हत्या के दो संदिग्ध उदयपुर से अजमेर की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी की और उन्होंने आरोपियों का पैदल भी पीछा किया। इस दौरान सूचना मिली कि, आरोपी भीम हाइवे पर है। जिस पर वे वापस गाडी में आए और दो आरोपी मो.रियाज अत्तारी

(शेष पृष्ठ 5 पर)

कर्नाटक में मांग उठी कि, तीन और डिप्टी सी.एम. बनाये जायें

ये उपमुख्यमंत्री एस.सी.,एस.टी व बैकवर्ड जाति के हों

- मामला जटिल है, क्योंकि जब डी.के. शिवकुमार ने अपना मु.मंत्री पद का दावा छोड़ा था तो शर्त रखी थी कि, वे डिप्टी सी.एम. का पद पाकर संतुष्ट हो जायेंगे, पर, कर्नाटक में केवल एक ही उपमुख्यमंत्री होगा, और उनकी यह शर्त हाईकमान ने स्वीकार की थी।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। एक वर्ष से अधिक के असंतोष के बाद, कर्नाटक मंत्री परिषद में कांग्रेस के महत्वाकांक्षी मंत्रियों ने पदोन्नति के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं और वे उपमुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नत करने की मांग कर रहे है वे इस मामले के ''उचित निर्णय'' के लिए पहुँचने वाले हैं।

कांग्रेस केन्द्र सरकार बनाने का मौका चूक गई क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुमत के आँकड़े से पिछड़ गया, 40 सीटें कम रह गई, इसके बाद प्रदेश के मंत्रियों व विधायकों को केन्द्रीय नेतृत्व पर दबाव डालना शुरू करने के लिए थोड़ा और साहसी होने का मौका मिल गया। खासतौर से यह दबाव विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं की तरफ से आ रहा है, वे अपनी राजनीतिक जोर आज़माइश कर रहे हैं और भाजपा सत्ताधारी पार्टी में दरार पैदा होने की प्रतीक्षा कर रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री बसवाराज बोम्मई एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाय. विजयेन्द्र पहले से ही भविष्यवाणी करते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जल्दी ही गिरने वाली है, जबकि 135 सीटें जीतकर भारी बहुमत में होने के बाद ऊपरी तौर पर कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री पद के दो तगड़े दावेदार है और भाजपा यह कयास लगा रही है कि इन दोनों के बीच मतभेद के चलते अन्ततोगत्वा उसे अपना खेल खेलने का मौका मिलेगा। परन्तु भाजपा यह भी अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस के पास राज्य विधानसभा में प्रचंड बहुमत होने के कारण उसके लिए कर्नाटक में सफलतापूर्वक ''ऑपरेशन लोटस'' पूरा करना बहुत ही मुश्किल कार्य है।

जरूरी वस्तुओं की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी तथा पैट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स में वृद्धि है के कारण असंतोष बढ़ रहा है कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को यह सोचना पड़ रहा है कि अंदरूनी कलह तथा धड़ेबाजी से निपटने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए।

अब सात मंत्रियों का एक दल दिल्ली चलो अभियान की योजना बना रहा है ताकि वे वहाँ कैबिनेट में उनका दर्जा बढ़ाने की मांग रख सके। वर्तमान में, सरकार में सिर्फ एक उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हैं और उनकी यह शर्त है कि वे ही एकमात्र उपमुख्यमंत्री रहेंगे, तब ही उन्होंने सिद्धारैमया को मुख्यमंत्री पद देने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था।

मंत्रिगण हाईकमान को इस बात से प्रभावित करना चाहते है कि (डी.के.एस.) के वोक्कालिगा समुदाय के अतिरिक्त अन्य समुदाय जैसे कि एस.सी./एस.टी. समुदाय के नेताओं को भी उपमुख्यमंत्री पद मिलने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। गृह मंत्री डॉ.जी. परमेश्वरा, सहकारी मंत्री के.एन. राजन्ना, लोक कार्य मंत्री सतीश जारकिहोली एवं अल्प संख्यक मामलात मंत्री बी.ज़ैड ज़मीर अहमद खान जैसे वरिष्ठ नेतागण उन्हें पदोन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर दबाव बढ़ा रहे हैं।

अब तीन और उपमुख्यमंत्री पदों की मांग की जा रही है वह एस.सी., एस.टी. तथा पिछड़ा वर्ग के लिए एक-एक।

राजन्ना, जो खुद को डिप्टी सी.एम.

(शेष पृष्ठ 5 पर)

पंजाब में ''ऑपरेशन लोटस'' की शुरुआत हुई?

पांच वरिष्ठ अकाली दल के नेताओं ने जालंधर में बैठक कर पार्टी अध्यक्ष को हटाने की मांग की

- इन बागी नेताओं का कहना है, गत लोकसभा चुनाव में पार्टी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। पार्टी का वोट प्रतिशत, जो 2019 में 27.42 था, अब घटकर लोकसभा चुनाव में केवल 13.42 प्रतिशत ही रह गया है। अतः पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन करने की जरूरत है।
- दूसरी ओर पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर, जो लोकसभा के चुनाव में जीती अकाली दल की एकमात्र सांसद हैं, ने कहा कि, ये पांच बागी नेता भाजपा के संपर्क में हैं, तथा इनको सबक लेना चाहिए महाराष्ट्र से, जहां उद्धव ठाकरे को छोड़कर भाजपा के साथ जाने वाले शिव सेना के नेताओं का लोकसभा चुनाव में क्या हश्र हुआ है। भाजपा का ''ऑपरेशन लोटस'' पंजाब में कभी सफल नहीं होगा, तथा साथ ही अब किसी भी हालत में अकाली दल भाजपा से हाथ नहीं मिलायेगा, पंजाब में।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। ओम बिड़ला के लोकसभा स्पीकर पद पर पुनः निर्वाचन के बीच एन.डी.ए. गठबंधन के एक पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (एस.ए.डी.) ने भाजपा पर पंजाब में ''ऑपरेशन लोटस'' चलाने के प्रयास का आरोप लगाया है।

एस.ए.डी. की आंतरिक समस्याओं में उबाल तब आ गया जब पार्टी के कुछ असंतुष्ट एवं अति सक्रिय नेताओं के एक गुट ने पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल द्वारा आप चंडीगढ़ में आयोजित एक मीटिंग के विरोध में अलग एक मीटिंग आयोजित कर दी। असंतुष्ट गुट के नेताओं में पूर्व सांसद एवं एस.ए.डी. के सचिव प्रेम सिंह चंदूमाजरा सहित पार्टी के पाँच सीनियर नेता हैं। इन नेताओं ने जालंधर में एक समानान्तर मीटिंग आयोजित कर मांग की कि, हाल ही सम्पन्न लोकसभा चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की जिम्मेवारी लेते हुए बादल को इस्तीफा दे देना चाहिए।

उक्त समानांतर मीटिंग में चन्दूमाजरा के अलावा सिकन्दर सिंह मलुका, बीबी जागीर कौर, परमिन्दर ढींढ़सा और स्वर्ण सिंह किल्लौर मौजूद थे। बागी नेताओं ने अगले माह से एस.ए.

(शेष पृष्ठ 5 पर)

जे.डी.ए. को निर्माण नहीं तोड़ने के आदेश

जयपुर, 26 जून (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की न्यू सांगानेर रोड की चौडाई दो सौ फीट करने के दौरान याचिकाकर्ताओं के निर्माण तोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में जेडीए के सचिव, प्रवर्तन अधिकारी, पीआरएन साउथ-प्रथम व डिप्टी

- राजस्थान हाई कोर्ट ने रोहित कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, याचिकाकर्ता अतिक्रमणकारी नहीं हैं। मामले की सुनवाई 5 जुलाई को होगी।

कमिश्नर को जवाब देने के आदेश दिए हैं और मामले की सुनवाई 5 जुलाई को तय की है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश रोहित कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एमएस राघव ने अदालत को

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'भारत में जी.डी.पी. ग्रोथ रेट 8 प्रतिशत'

- रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह जानकारी देते हुए कहा कि, इसकी तुलना में चीन की ग्रोथ रेट 5 प्रतिशत रहने की संभावना है।
- दास ने मुम्बई में एक आयोजन में यह भी कहा कि, भारत की इतनी अच्छी ग्रोथ रेट का कारण है, जी.एस.टी. तथा इन्सॉल्वैंसी एण्ड बैंकरप्सी कोड व फ्लैक्सिबल इन्फ्लेशन टारगैटिंग मॉडल का क्रियान्वयन।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। भारत 8 प्रतिशत की एक सतत जी.डी.पी. वार्षिक वृद्धि को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह कहना है रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया (आर.बी.आई.) के गवर्नर शक्तिकांत दास का। दास मुम्बई के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत चीन की अर्थव्यवस्था के प्रति वर्ष 5 प्रतिशत वार्षिक के आस-पास आगे बढ़ने की उम्मीद है।

दास ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए आर.बी.आई. की 7.2 प्रतिशत जी.डी.पी. वृद्धि की भविष्यवाणी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत जी.डी.पी. की एक टिकाऊ 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखते हुए अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव के कगार पर है।

महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के बल पर पिछले तीन वर्षों में भारत की जी.डी.पी. औसतन 8.3 प्रतिशत रही है। आर्थिक विकास में वृद्धि करने वाले प्रमुख पहलुओं के रूप में दास ने गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) व द इन्सॉलवैंसी एण्ड बैंक्रेप्सी कोड (आई.बी.सी.) को लागू करने तथा महंगाई के एक लचीले मॉडल का उल्लेख किया। दास ने कहा कि ''अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक सुधारों में सबसे प्रमुख जी.एस.टी. है। यह टैक्स पर टैक्स और उससे पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों को रोकता है। मेरी नज़र में स्वतंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों में जी.एस.टी. एक है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि 1.5 से 1.7 ट्रिलीयन रूपए प्रतिमाह के जी.एस.टी. कलैक्शन ने कारोबार में प्रभावी वृद्धि की है।

इसके अलावा, दास ने उल्लेख किया कि भारत की खुदरा महंगाई दर कम हो रही है, लेकिन यह कमी शनैः-शनैः हो रही है। रिज़र्व बैंक सजग है क्योंकि मौसम की एक भी मार खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि कर सकती है।

दास ने कहा कि भारत की जी.डी.पी. में पिछले तीन वर्षों में 8.3 प्रतिशत की औसतन वृद्धि रही है।

इसके विपरीत, चीन की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 5.3 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ी, जबकि वर्ष 2023 की अंतिम तिमाही के दौरान बाजार की भविष्यवाणी 5 से 5.2 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि की थी। यह बीजिंग के निरन्तर सहयोग उपायों और चन्द नव वर्ष उत्सव से संबंधित व्यय के कारण 2023 की दूसरी तिमाही के बाद से सबसे बड़ा वार्षिक विस्तार था। वर्ष 2024 के प्रथम तिमाही के दौरान स्थिर निवेश 4.5 प्रतिशत बढ़े जो कि करीब एक साल में सर्वाधिक थे और 4.3 प्रतिशत की सर्वसम्मति से अधिक थे।

इस बीच, चीन के नैशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ने इस वर्ष करीब 5 प्रतिशत की जी.डी.पी. वृद्धि का लक्ष्य रखकर एक अच्छी शुरूआत की है। तथापि, मार्च माह के डेटा से पता चला है कि औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री में अनुमान से कम वृद्धि हुई, यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए अधिक नीतिगत सरलताएं लाना लाज़िमी बना हुआ है। इसके साथ ही, चिन्हित बेरोज़गारी दर मार्च माह में 5.2 प्रतिशत पर आ गई जबकि फरवरी माह में यह गत सात महीनों में सर्वाधिक 5.3 प्रतिशत थी। इसमें चन की युवा बेरोज़गारी दर शामिल नहीं है जो जून 2023 में 21.3 प्रतिशत की रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी।

एक्सिस बैंक पर 31,000 रूपए का जुर्माना

जयपुर, 26 जून (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने लोन के बदले बैंक में गिरवी रखे संपत्ति के दस्तावेज खोने को गंभीर सेवा दोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने एक्सिस बैंक पर 31 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग ने बैंक को निर्देश दिए हैं कि वह एक माह में परिवादी को संपत्ति के मूल दस्तावेज लौटाए। ऐसा नहीं करने पर बैंक को क्षतिपूर्ति के तौर पर तीस लाख रुपए अदा करने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश संगीता शर्मा के परिवाद को मंजूर करते हुए दिए।

आयोग ने कहा कि, बैंक ने परिवादी को मॉरगेज लोन दिया था और उसकी एवज में संपत्ति के दस्तावेज अपने पास बंधक रखे थे, लेकिन लोन की एनओसी जारी करने के बाद

- जिला उपभोक्ता न्यायालय ने लोन के बदले गिरवी रखे गए फ्लैट के दस्तावेज गुम होने को एक्सिस बैंक का गंभीर सेवा दोष माना।

दस्तावेज नहीं लौटाना और खो देना गंभीर है। ऐसे में दस्तावेज खोने से परिवादी को मानसिक आघात लगा है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए विपक्षी से 30 लाख रुपए दिलवाना उचित होगा।

मामले के अनुसार, परिवादी और उसके पति उमेश शर्मा ने 21 फरवरी 2012 को कनकपुरा, सिरसी रोड स्थित अपार्टमेंट में 19.40 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा था। इस फ्लैट पर उन्होंने बैंक से लोन लिया और उसके दस्तावेज बैंक में जमा करवा दिए। इसके बाद परिवादी लोन की किस्तों का नियमित भुगतान करता रहा। कोविड के दौरान मार्च 2022 में परिवादी के पति का निधन हो गया। जिस पर उसने इंश्योरेंस से प्राप्त क्लेम राशि से लोन की समस्त बकाया राशि चुका दी और बैंक

(शेष पृष्ठ 5 पर)

नीट पेपर लीक, दो आरोपी सी.बी.आई. को सौंपे

पटना, 26 जून। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के प्रश्न-पत्र

- कोर्ट ने जेल में बंद दोनों अभियुक्तों, बलदेव उर्फ चिंटू तथा मुकेश को 4 जुलाई तक के लिए सी.बी. आई. को रिमांड पर दिया है।

लीक मामले में जेल में बंद दो अभियुक्तों को एक सप्ताह की पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।

सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत ने यह आदेश सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया है। विशेष अदालत

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'एक मिनट के साइलैंस की व्यवस्था के अलावा दो-तीन और घटनाएं भी थीं, जिन्होंने भाईचारे का माहौल खराब किया प्रथम दिन'

लोकसभा अध्यक्ष ने इन घटनाओं पर सख्ती का रूख रखा, और उन सांसदों को चुप कराया

- अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने जब ''उन सांसदों पर कटाक्ष किया, जिन्होंने अपनी ''आइडियोलॉजी'' (राजनीतिक सिद्धांत) को तिलांजलि दी, चुनाव जीतने के लिये, तो, स्पीकर ने उनसे कहा, सदन के प्रथम दिन राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं।
- होशियारपुर से निर्वाचित, आप के सांसद राजकुमार खंडेलवाल ने जब यह मुद्दा उठाया कि, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया, तो नवनिर्वाचित स्पीकर ने उन्हें बैठने का आदेश दिया।
- श्रीनगर से निर्वाचित सांसद आगा मेहंदी ने जब यह आरोप लगाया कि, संविधान की धारा 370, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती है, को रद्द करने वाला विधेयक आधे घंटे में पारित कर दिया गया था, लोकसभा में, तो स्पीकर ने सख्ती से उन्हें कहा कि, यह कथन असत्य है, क्योंकि इस मुद्दे पर सदन में नौ घंटे बहस हुई थी और उसके बाद ही बिल पारित हुआ था।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच ओम बिड़ला को स्पीकर बनाने के लिए जो सद्भाव बना था वह क्षणिक ही रहा। नव निर्वाचित स्पीकर ने आपातकाल के दिनों की याद में सांसदों को दो मिनट का मौन रखने का आदेश देकर सारा माहौल बिगाड़ दिया।

इससे पहले एन.डी.ए. के प्रत्याशी ओम बिड़ला को लोकसभा स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। बिड़ला के चयन के साथ प्रो-टैम स्पीकर ने कहा कि ''इसी के साथ विपक्ष के प्रत्याशी के.सुरेश की उम्मीदवारी का प्रस्ताव रद्द हो जाता है। मैं ओम बिड़ला को स्पीकर के पद पर निर्वाचित घोषित करता हूँ।''

इसके बाद मोदी और संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजीजू सत्ता पक्ष की अग्रिम पंक्ति में बैठे ओम बिड़ला के पास गए इसमें उनके साथ राहुल गाँधी भी थे। राहुल गाँधी ने बिड़ला का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया।

इसके बाद मोदी, राहुल और रिजीजू बिड़ला को आसन तक ले गए जहाँ मेहताब ने उनसे कहा कि यह आपकी कुर्सी है, कृपया इसे ग्रहण करें।

प्रधानमंत्री ने कहा आपका इस पद पर लगातार दूसरी बार निर्वाचित होना सम्मान की बात है। मैं आपको समूचे सदन की तरफ से बधाई देता हूँ, और उम्मीद है कि आगामी साल तक हमे आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा।

अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि सांसद के रूप में बिड़ला का कार्यकाल नई लोकसभा के सदस्यों के लिए प्रेरणादायक रहेगा।

मोदी ने कहा, आज़ादी के सत्तर साल में जो काम कभी नहीं हुए वो आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने किए। लोकतंत्र की लम्बी यात्रा में कई पड़ाव आए। और कई अवसर ऐसे थे जब हमें मौका मिला, नई इबारत गढ़ने का। मुझे यकीन है कि देश 17वीं लोकसभा की उपलब्धियों पर गर्व करेगा। मोदी ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नए अपराधिक कानूनों, जम्मु कश्मीर पुनर्गठन एवं धारा 370 रद्द करने संबंधी विधेयकों का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री के बाद राहुल गाँधी बोलने के लिए उठे। उन्होंने बिड़ला को दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी, और कहा कि उन्हें भरोसा है कि स्पीकर विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का अवसर देंगे। मैं आपको समूचे विपक्ष और इंडिया गठबंधन की तरफ से बधाई देता हूँ। स्पीकर सर, यह सदन भारत की जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और आप इस आवाज़ का अंतिम ज़रिया हैं।

उन्होंने आगे कहा, ''निश्चित रूप से सत्तापक्ष के पास राजनैतिक ताकत है, पर विपक्ष

(शेष पृष्ठ 5 पर)